GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.67
TO BE ANSWERED ON 22ND JULY, 2022

DISTRIBUTION OF FORTIFIED RICE UNDER PDS, PM-POSHAN AND ICDS

67. SHRI PRABHAKAR REDDY VEMIREDDY:

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government has started a pilot project for distributing fortified rice through Public Distribution System (PDS), PM-POSHAN, Integrated Child Development Services (ICDS), etc.;

(b) if so, the details of districts identified, State-wise, and the status of implementation of the project;

(c) whether it is also a fact that Government has decided to distribute only fortified rice through PDS by 2024;

(d) if so, the status of preparation and whether Government will achieve the target; and

(e) the details of rice required to achieve the 2024 goal and how Government is planning to procure it?

A N S W E R
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (**SHRI ASHWINI KUMAR CHOUBEY**)

(a) to (e): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) to (e) OF THE STARRED QUESTION NO. *67 FOR ANSWER ON 22.07.2022 IN THE RAJYA SABHA.

(a): Yes Sir. To address anaemia and micro-nutrient deficiency in the country, the Government of India had approved the Centrally Sponsored Pilot Scheme on "Fortification of Rice & its Distribution under Public Distribution System" on 14th February, 2019, for a period of 3 years beginning 2019-20.

(b): Fifteen State Governments (with Districts) i.e. Andhra Pradesh (Vizianagram), Kerala (Ernakulum), Karnataka (Yadgir or Mysore), Maharashtra (Gadchiroli), Odisha (Malkangiri), Gujarat (Narmada), Uttar Pradesh (Chandauli), Assam (Dhubri), Tamil Nadu (Tiruchirappalli/Trichy), Telangana (KumrabheemAsifabad or Jayashankar Bhupalapally or Khammam), Punjab (Gurdaspur/Ludhiana), Chhattisgarh (Kondagaon), Jharkhand (East Singhbhum), Uttarakhand (Udham Singh Nagar) and Madhya Pradesh (Singrauli) had consented and identified their respective Districts for implementation of the Pilot Scheme. Approximately 4.30 Lakh Metric Ton (LMT) of fortified rice has been distributed through PDS under the Pilot Scheme till 2021-22, in eleven States except Assam, Karnataka, Kerala and Punjab.

(c) & (d): Yes Sir. The Government has approved the supply of fortified rice throughout the Targeted Public Distribution System (TPDS) under the National Food Security Act (NFSA) and in Other Welfare Schemes of Government of India in all States and Union Territories (UTs) in a phased manner by the year 2024. The FCI and State Agencies have commenced the procurement of fortified rice.

(e) Nearly 350 LMT of fortified rice is required for distribution in all Government Schemes including TPDS, ICDS, PM-POSHAN and Other Welfare Schemes (OWSs) by 2024. FCI and State Agencies have already procured around 138 LMT of Fortified Rice so far. Instructions have been issued to all States/UTs to build up necessary infrastructure for rice fortification and to ensure adherence to deadline with regular monitoring.

*****

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 67

22 जुलाई, 2022 के लिए प्रश्न

पीडीएस, पीएम-पोषण और आईसीडीएस के अधीन पुष्टीकृत (फोर्टीफाइड) चावल का वितरण

***67. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), पीएम-पोषण, एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस), आदि के माध्यम से पुष्टीकृत चावल के वितरण के लिए एक प्रायोगिक परियोजना की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो पहचान किए गए जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने वर्ष 2024 तक पीडीएस के माध्यम से केवल पुष्टीकृत चावल के वितरण का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तैयारी की स्थिति क्या है और क्या सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी; और

(ड) वर्ष 2024 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित चावल का ब्यौरा क्या है और सरकार इसे किस प्रकार खरीदने की योजना बना रही है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

राज्य सभा में दिनांक 22 जुलाई, 2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 67 के उत्तर के भाग (क) से (ड.) में उल्लिखित विवरण

(क): जी हां। देश में रक्ताल्पता (अनीमिया) और सूक्ष्म पोषक तत्वों (माइक्रो-न्यूट्रीएंट) की कमी का समाधान करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 से प्रारंभ करके 3 वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 14 फरवरी, 2019 को "चावल का फोर्टिफिकेशन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इसका वितरण" संबंधी केंद्रीय प्रायोजित पायलट स्कीम को स्वीकृति दी थी।

(ख): पायलट स्कीम के कार्यान्वयन हेतु पन्द्रह राज्य सरकारों (जिले सहित) अर्थात आंध्र प्रदेश (विजयनगरम), केरल (एर्नाकुलम), कर्नाटक (यादगीर अथवा मैसूर), महाराष्ट्र (गढ़चिरौली), ओडिशा (मलकानगिरी), गुजरात (नर्मदा), उत्तर प्रदेश (चंदौली), असम (धुबरी), तमिलनाडु (तिरुचिरापल्ली/त्रिची), तेलंगाना (कोमराभीम आसिफाबाद अथवा जयशंकर भूपलपल्ली अथवा खम्माम), पंजाब (गुरदासपुर/लुधियाना), छत्तीसगढ़ (कोंडागांव), झारखण्ड (पूर्व सिंहभूम), उत्तराखंड (उधम सिंह नगर) और मध्य प्रदेश (सिंगरौली) ने सहमति दी थी और अपने अपने जिलों को चिह्नित किया था। असम, कर्नाटक, केरल और पंजाब को छोड़कर 11 राज्यों में, वर्ष 2021-22 तक पायलट स्कीम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए लगभग 4.30 लाख टन फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया गया।

(ग) और (घ): जी हां। सरकार ने वर्ष 2024 तक चरणबद्ध तरीके से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी स्कीमों के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के जरिए फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की है। भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों ने फोर्टिफाइड चावल की खरीद की शुरुआत कर दी है।

(ड.): वर्ष 2024 तक टीपीडीएस, आईसीडीएस, पीएम-पोषण और अन्य कल्याणकारी स्कीमों (ओडब्ल्यूएस) सहित सभी सरकारी स्कीमों में वितरण हेतु लगभग 350 लाख टन फोर्टिफाइड चावल अपेक्षित है। अब तक भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों ने लगभग 138 लाख टन फोर्टिफाइड चावल की खरीद कर ली है। चावल के फोर्टिफिकेशन के लिए आवश्यक आधारभूत अवसंरचना का निर्माण करने और नियमित निगरानी के साथ समय-सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश जारी किए गए हैं।

*****

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Any supplementaries?

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA: Thank you Mr. Deputy Chairman, Sir. ...*(Interruptions)*... On behalf of Shri Prabhakar Reddy Vemireddy, I would.....*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not on his behalf, but as a separate question. ...*(Interruptions)*... You have a right to ask. ...*(Interruptions)*...

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA: Thank you, Sir. ...*(Interruptions)*... मंत्री महोदय से मेरा क्वश्चन है the End-to-End Computerization of Targeted Public Distribution System Operations including automation of Fair Price Shops seek to bring transparency and efficiency in the allocation and distribution of highly subsidized food grains to the beneficiaries. I want to ask the hon. Minister as to what is the present status of the scheme in Andhra Pradesh.

श्री अश्विनी कुमार चौबे : उपसभापति महोदय, प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य, रेड्डी जी ने जो प्रश्न किया है, ...**(व्यवधान)**... मैं उसके संदर्भ में बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने पूरी तरह से ...**(व्यवधान)**... आदरणीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने जो पौष्टिकृत आहार, फोर्टिफाइड राइस के बारे में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह घोषणा की, ...**(व्यवधान)**... उसके तहत हमने 65 प्रतिशत ऐसे लोग, जो देश में चावल खाते हैं, ...**(व्यवधान)**... उनके लिए पूरी व्यवस्था की। ...**(व्यवधान)**... हमने उनकी जनसंख्या को देखते हुए, ...**(व्यवधान)**... और देश में जो सर्वाधिक वंचित और समाज के ऐसे कमजोर वर्ग के लोग हैं, ...**(व्यवधान)**... उनके लिए, जो कुपोषण के शिकार होते हैं, ...**(व्यवधान)**... उनको बचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। ...**(व्यवधान)**... महोदय, प्रश्नकर्ता सदस्य का मैंने पूरा स्पष्ट उत्तर ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : आप संक्षेप में जवाब दें। ...**(व्यवधान)**...

श्री अश्विनी कुमार चौबे : अगर फिर से ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री, पीयूष गोयल जी, प्लीज़। ...**(व्यवधान)**...

वाणिज्य और उद्योग मंत्री; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री; तथा वस्त्र मंत्री (**श्री पीयूष गोयल**) : माननीय उपसभापति महोदय, सांसद महोदय ने जो पूछा, ...**(व्यवधान)**... उस संदर्भ में अभी तक आन्ध्र प्रदेश को 43,000 टन का टोटल एलोकेशन हुआ है, ...**(व्यवधान)**... जिसमें से अभी तक उसने 27,590 टन ले लिया है, लिफ्टिंग कर ली है। ...**(व्यवधान)**... प्रधान मंत्री-पोषण अभियान, ...**(व्यवधान)**... पहले मैंने आईसीडीएस का नंबर दिया है, प्रधान मंत्री-

पोषण अभियान के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश को 86,526 टन का एलोकेशन हुआ है, out of which the lifting under PM-POSHAN under Andhra Pradesh is 78,378. ...*(Interruptions)*... I am happy that they are implementing it. ...*(Interruptions)*... We are now looking at converting the entire rice to fortified rice which is in the interest of the country and will help reduce the incidence of malnutrition. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : डा. के. लक्ष्मण जी। ...(**व्यवधान**)...

डा. के. लक्ष्मण : उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि whether it is a fact that the TRS Government has miserably failed to implement the PDS in Telangana. ...*(Interruptions)*... मोदी जी की सरकार के द्वारा देश भर में गरीबों के हित के लिए, ताकि कोई गरीब भूखे पेट न सोए, 80 करोड़ आबादी को 5 किलो चावल दिया जा रहा है, ...(**व्यवधान**)... मगर तेलंगाना के अन्दर अप्रैल माह से सभी फ्री राशन बंद किया गया। ...(**व्यवधान**)... क्या यह सही है? What is the action taken by the Union Government to see that the free ration reaches the poor people of Telangana?. ...*(Interruptions)*...

श्री पीयूष गोयल : माननीय उपसभापति महोदय, बहुत दुर्भाग्य से पिछले कुछ महीनों में यह स्थिति उत्पन्न हुई, ...(**व्यवधान**)... जिसके कारण तेलंगाना में हमारी जो अन्यान्य योजनाएँ हैं, उनमें उसने पूरे तरीके से अपना योगदान नहीं दिया। ...(**व्यवधान**)... उदाहरण के लिए, अभी जो राइस फोर्टिफिकेशन का कार्यक्रम चल रहा है, ...(**व्यवधान**)... केन्द्र सरकार, ...(**व्यवधान**)... प्रधान मंत्री, मोदी जी की इच्छा थी कि बच्चों को, ...(**व्यवधान**)... जो हमारी माताएँ हैं, उनको आईसीडीएस और पीएम-पोषण के अंतर्गत जो चावल मिलता है, वह फोर्टिफाइड राइस मिले। ...(**व्यवधान**)... इस उद्देश्य से तेलंगाना को आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत 26,180 टन चावल उठाना था, उसके सामने उसने मात्र 6,544 टन ही उठाया। ...(**व्यवधान**)... ऐसे ही पीएम-पोषण के अंतर्गत तेलंगाना को 16,499 टन चावल लेना था, लेकिन अभी तक उसने शून्य, दुर्भाग्य से शून्य फोर्टिफाइड चावल लिया है। ...(**व्यवधान**)... वैसे तो प्रधान मंत्री जी ने संवेदना दिखाते हुए देश के 80 करोड़ लोगों के लिए, ...(**व्यवधान**)... प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो मुफ्त में राशन दिया, ...(**व्यवधान**)... फूड सिक्योरिटी के अतिरिक्त, ...(**व्यवधान**)... हर व्यक्ति के लिए 5 किलो अतिरिक्त राशन दिया। ...(**व्यवधान**)... 25 महीने तक, ...(**व्यवधान**)... उसमें भी अप्रैल से जो राशन देना था, उसमें तेलंगाना सरकार ने बहुत सुस्ती दिखाई। ...(**व्यवधान**)... उसके कारण अप्रैल से वहाँ के गरीबों को प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो अधिक अनाज मिलना था, वह नहीं मिल रहा है। ...(**व्यवधान**)... केन्द्र सरकार ने इसको बहुत सख्ती से लिया, तब जाकर तेलंगाना सरकार ने जून महीने के अनाज का वितरण बड़ी मुश्किल से हमारे बार-बार कहने के बाद शुरू किया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, आप briefly उत्तर दें। ...(**व्यवधान**)...

श्री पीयूष गोयल : अब हम उम्मीद करेंगे कि वे आगे केन्द्र सरकार की योजनाओं के साथ जुड़ेंगे। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now Shri G.V.L. Narasimha Rao. Please be brief in your question. *...(Interruptions)...*

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, I would like to first of all congratulate the hon. Prime Minister *...(Interruptions)...*and the Ministry for fortification of the PDS rice to end Anaemia and malnutrition. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please ask your question. *...(Interruptions)...*

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: My question to the hon. Minister is *...(Interruptions) ...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. *...(Interruptions)...* Do not do this. *...(Interruptions) ...* This is not proper. *...(Interruptions)...* This is not proper, Madam. ...(Interruptions)... Please. *...(Interruptions)...*

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: I will give privilege notice, if anybody disturbs me *...(Interruptions)...* Sir, my question to the hon. Minister is this. *...(Interruptions)...* Like the Government of Telangana, *...(Interruptions)...* even in Andhra Pradesh, free ration under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana had not been given to the people of Andhra Pradesh. *...(Interruptions)...* I have also written to the hon. Minister in this regard. *...(Interruptions)...* I would like to know from the hon. Minister as to what steps the Government has taken to ensure that the people of Andhra Pradesh also get this benefit*...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. *...(Interruptions)...*

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, we are in dialogue with the Government of Andhra Pradesh to ensure that *...(Interruptions)...*the poor people of Andhra Pradesh also get rice, free foodgrains under the PMGKAY. *...(Interruptions)...* We are in dialogue with them and we are hopeful that that will start soon*...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 68; questioner not present.

*68. [*The questioner was not present.*]